प्रगतिशील परिवर्तन :—

संवृद्धि के साथ-साथ आर्थिक विकास की अवधारणा में अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ ऐसे परिवर्तनों का भी समावेश है जो उसे प्रगतिशील बनाते हैं। भौतिक वस्तुओं और लोक-कल्याण की दृष्टि से ये परिवर्तन अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाते हैं और उसे आधुनिक रूप प्रदान करते हैं। यहाँ इन जैसे परिवर्तनों का उल्लेख किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, संवृद्धि को आर्थिक विकास कहलाने के लिए, उत्पादन और व्यवसाय के संबंध में विकसित देशों के अनुरूप आर्थिक संरचना में आवश्यक परिवर्तन आए। जहाँ तक उत्पादन की बात है, देश के कुल उत्पादन में उद्योग और सेवा क्षेत्रों का भाग बढ़ा तथा कृषि-क्षेत्र के भाग में कमी

(5)

पाए। इन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन आना चाहिए। अर्थात् कृषि-क्षेत्र में लगे श्रमिकों के अनुपात में कमी आए तथा उद्योग व सेवाओं में लगे श्रमिकों का अनुपात बढ़े।

आर्थिक संरचना में परिवर्तनों के अतिरिक्त, विकास की अवधारणा में संवृद्धि-अनुकूल संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तनों का भी समावेश है। ये परिवर्तन देश की संवृद्धि के अनुकूल परिवेश के सृजन में सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में, संवृद्धि के रास्ते में बाधक संस्थाओं और तकनीक का प्रगतिशील संस्थाओं और उन्नत तकनीक द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। अल्पविकसित देशों की संवृद्धि को भली प्रकार बनाए रखने के लिए ऐसे परिवर्तन विशेष महत्व रखते हैं।

इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यदि संवृद्धि के साथ गरीबी, बेरोजगारी और असमानताओं में कमी नहीं होती, तो यही सही अर्थ में यह आर्थिक विकास नहीं ठहरेगा। पांचवे और छठे दशक के दौरान अल्पविकसित देशों के अनुभव से इस विचारधारा को विशेष बल मिला। इस अवधि में संवृद्धि के बावजूद अनेक अल्पविकसित देशों में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता में कोई कमी नहीं आई। बल्कि अनेक स्थानों पर इस संबंध में स्थिति और बिगड़ गई। अतः यह विचार रखा जाने लगा कि विकास कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि संवृद्धि गरीबों के हित को बढ़ावा दे और न्याय-संगत हो।

पृथक्करण और अंतर :

आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणाएँ कई बातों में एक-दूसरे से अलग या भिन्न हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि से संवृद्धि का क्षेत्र सीमित या संकुचित है और विकास का विस्तृत। संवृद्धि की अवधारणा का संबंध केवल उत्पादन में परिवर्तनों के साथ है। इसका एकमात्र केन्द्र-बिन्दु उत्पादन-मात्रा और उसकी वृद्धि-दर है।

Scanned with CamScanner

इसके विपरीत विकास का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। संवृद्धि के अतिरिक्त, इसमें आर्थिक जीवन-संबंधी अन्य अनेक पहलुओं का समावेश है, जैसे कि जीवन-स्तर, रोजगार, वितरण, संस्थाएँ, तकनीक आदि। अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिकता की दृष्टि से भी ये दोनों अवधारणाएं एक-दूसरे से भिन्न है। विकसित देशों के लिए संवृद्धि की अवधारणा अधिक उपयुक्त या सुसंगत ठहरती है। यहां आर्थिक जीवन के विभिन्न आयाम पहले से ही विकसित अवस्था में हैं। लोगों के समृद्ध आर्थिक जीवन को और बेहतर बनाने के लिए यहां जो आवश्यक चीज है वह है उत्पादन-मात्रा में वृद्धि लाना और उसे बनाए रखना। इस कारण इन देशों के लिए संवृद्धि अवधारणा महत्वपूर्ण ठहरती है। अल्पविकसित देशों की स्थिति भिन्न है। यहां संवृद्धि परमावश्यक है, लेकिन यह अपने-आप में काफी नहीं है। इन देशों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए, उत्पादन में वृद्धि लाने के अतिरिक्त यहां आवश्यकता इन अनेक बातों की है — आर्थिक संरचना में अनुकूल परिवर्तन, संस्थागत सुधार, तकनीक के स्तर को ऊपर उठाना, वितरण को न्याय-संगत बनाना आदि। इस प्रकार इन देशों के लिए आर्थिक विकास की अवधारणा अधिक प्रासंगिक है।

विकसित और अल्पविकसित देशों की समस्याओं और उनके समाधान के दृष्टिकोण से भी दोनों अवधारणाएँ एक-दूसरे से अलग हैं। विकसित देशों के संदर्भ में संवृद्धि के सिलसिले में मुख्य रूप से इन जैसे कारकों पर ध्यान केन्द्रित करना होता है — व्यापार चक्र, मांग, बाजार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके विपरीत अल्पविकसित देशों में समस्याओं का स्वरूप केवल आर्थिक ही नहीं होता, बल्कि समस्याएँ सामाजिक और राजनीतिक भी होती हैं। इस कारण यहां संवृद्धि की समस्या और उसके समाधान को अधिक व्यापक रूप में और आधार पर देखना होता है। रीति-नीति में भिन्नता होती है उदाहरण

(४)

के लिए, विकसित देशों में समस्या प्रमुख रूप से माँग पक्ष से जुड़ी होती है, जबकि अल्पविकसित देशों में मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करना होता है। वहाँ अल्पविकसित देशों के संदर्भ में सरकार का सक्रिय योगदान विशेष महत्वपूर्ण ठहरता है।